पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA

स्वच्छ भारत
सम्पूर्ण स्वच्छता की ओर

स्वच्छता समाचार

मई 2024

स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण न्यूज़लेटर

@swachhbharat @SBMGramin @SwachhBharatMissionGramin @swachh_bharat @swachhbharatgrameen

स्वच्छता से स्वास्थ्य

स्वच्छता पखवाड़ा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

- 8 अप्रैल 2024 को वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में प्रदूषण और स्वास्थ्य पर प्रभाव के संबंध में सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किया गया।
- 3 अप्रैल 2024 को मेडिकल हॉस्टल परिसरों में स्वैच्छिक स्वच्छता श्रमदान आयोजित किया गया। वहां स्वच्छ छात्रावास शीर्षक के साथ सेल्फी बूथ स्थापित किया गया।
- 13 अप्रैल 2024 को वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, मौरिस नगर स्टाफ क्वार्टर में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया।
- 14 अप्रैल 2024 को NEB, SSB जोन-II बिल्डिंग में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल में सेनेटरी अधीक्षक/सेनेटरी इंस्पेक्टर द्वारा आम जनता के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- अस्पताल के संक्रमण नियंत्रण अधिकारी द्वारा BMW रिले ट्रॉली का उपयोग करके बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन नीतियों पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।

विधि और न्याय मंत्रालय

- कार्यालय में स्वेच्छा से सफाई की गई और सभी बेकार वस्तुओं को हटा दिया गया तथा भौतिक फाइलों को स्कैन करके ई-ऑफिस पर अपलोड कर दिया गया।
- अभिलेखों की सफाई की गई और 8 अप्रैल, 2024 को न्याय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।
- सचिव (न्याय) ने न्याय विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई, जिसके बाद स्वैच्छिक श्रमदान किया गया और बैनर तथा प्लाई निर्मित कार्ड प्रदर्शित किए गए।

राजस्थान में SLWM पर अभिनव प्रशिक्षण के माध्यम से स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे के कार्यान्वियन और संचालन एवं रखरखाव के कार्य में तेजी लाना

खुले में शौच मुक्त (ODF) प्लस स्थिति को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के अनुसरण में, राजस्थान ने ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (SLWM) संबंधी बुनियादी ढांचे के कार्यान्वियन और संचालन तथा रखरखाव (O&M) को मजबूत करने में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। राज्य ने, यूनिसेफ के सहयोग से, SLWM के कार्यान्वियन में तेजी लाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें SBM (G) - चरण I से सीख और SLWM प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वियन के दौरान राज्य और यूनिसेफ द्वारा किए गए साक्ष्य-आधारित क्षेत्र संबंधी निष्कर्षों और समीक्षाओं के माध्यम से एकत्रित की गई सामने आने वाली बाधाओं को शामिल किया गया।

जिला कलेक्टर के नेतृत्व में, केकड़ी, अजमेर और ब्यावर जिलों के कुल 60 प्रतिभागियों के साथ दो दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। यह तकनीकी और प्रशासनिक टीमों से सुसज्जित था जिसमें ऐसे सहायक अभियंता (AES), कनिष्ठ अभियंता (JES), कनिष्ठ तकनीकी सहयोगी (JTAS), खंड विकास अधिकारी (BDOS) और ब्लॉक समन्वयक (BC) शामिल थे, जिनके पास SLWM आयोजना, कार्यान्वियन और निगरानी के लिए आवश्यक स्थानीय रूप से प्रासंगिक जानकारी और आवश्यक कौशल थे।

प्रशिक्षण ने स्थानीय चुनौतियों का निराकरण कर दिया और लसाडिया गांव में राजस्थान "सैनिटेशन पार्क" के उद्घाटन की स्थापना का साक्षी बना, जिसमें SLWM संबंधी प्रौद्योगिकियों पर प्रकाश डाला गया जिन्हें जिले की प्रकृति और जनसांख्यिकी के अनुरूप घरेलू और सामुदायिक स्तर की संपत्तियों को कवर करते हुए तैयार किया गया था।

प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप प्रतिभागियों के बीच SLWM संचालन, कंपोस्ट खाद बनाने और सही निर्माण पद्धतियों की व्यापक समझ उत्पन्न हुई। सैनिटेशन पार्क में प्रदान की गई सामग्री के विस्तृत विवरण और जानकारी ने राजमिस्त्री सहित भागीदारों की क्षमता को बढ़ाया, जिससे वे SLWM अपनाने को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में उभरे। प्रशिक्षण ने जलवायु अनुकूल SLWM प्रथाओं के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई और पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए किए जा रहे रखरखाव के महत्व पर जोर दिया।

इस गति को आगे बढ़ाते हुए, राजस्थान SLWM प्रौद्योगिकियों के O&M को समर्थकारी बनाने और स्वच्छता पार्कों की पुनरावृत्ति के लिए निरंतर हितधारक क्षमता निर्माण (स्वच्छता कामगारों सहित) के माध्यम से प्रगति की गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री ऋषभ हेमानी, वॉश स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ, राजस्थान rhemani@unicef.org पर इनपुट के साथ

पर्यावरणीय पहलों को एकीकृत करना: जम्मू एवं कश्मीर के स्वच्छता बैंकों को एकजुट करना

कचरा प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के दृढ़ निश्चयी प्रयास में, जम्मू एवं कश्मीर के कई जिलों ने स्वच्छता बैंक के नाम से एक अभिनव पहल शुरू की है। जम्मू, श्रीनगर, ऊधमपुर और कुलगाम सहित विभिन्न जिलों में उद्घाटन किए गए ये बैंक प्लास्टिक कचरे के संग्रह स्थलों के रूप में काम करते हैं, और व्यक्तियों को जिम्मेदार कचरा निपटान प्रथाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

मिशन निदेशक, SBM (G) जम्मू एवं कश्मीर, सुश्री अनु मल्होत्रा के नेतृत्व में, स्वच्छता बैंक पहल का उद्देश्य कचरा प्रबंधन प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देते हुए उचित कचरा निपटान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नामित स्वच्छता बैंकों में प्लास्टिक कचरे को जमा करने के माध्यम से, व्यक्तियों को नकद, स्टेशनरी आइटम, टी-शर्ट और टोपी जैसे पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।

इन स्वच्छता बैंकों के उद्घाटन समारोह में स्थानीय अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्यों की उपस्थिति देखी गई, सभी ने इस पहल के लिए अपना दृढ़ समर्थन व्यक्त किया। जिला विकास सलाहकारों और सामुदायिक नेताओं ने इस पहल की नेक प्रकृति को महत्व देते हुए, कचरा प्रबंधन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्य की अनिवार्यता पर जोर दिया।

स्वच्छता बैंकों की पहल को और बल प्रदान करते हुए, भारतीय प्रदूषण नियंत्रण संघ (IPCA) के सहयोग से जम्मू जिले की पंचायत गाजीपुर कुल्लियां में "मेरा 10 किलो प्लास्टिक अभियान" शुरू किया गया है। यह अभियान व्यक्तियों को 10 किलो प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने और उसका निपटान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उन्हें प्रतिष्ठित "प्लास्टिक तटस्थ नागरिक प्रमाणपत्र" प्राप्त होता है।

स्वच्छता बैंकों की सफलता महज संग्रह प्रयासों से कहीं बढ़कर, जैसा कि शोपियां में स्वच्छता बैंक में हाल ही में हुई नीलामी से पता चलता है। ब्लॉक विकास कार्यालय (BDO), कांजीउल्लार द्वारा की गई नीलामी में प्लास्टिक प्रदूषण का निराकरण करने में समुदाय के सामूहिक प्रयासों को प्रदर्शित किया गया। 4 रुपये प्रति किलोग्राम से शुरू होने वाली बोलियों की परिणति एक सफल नीलामी के रूप में सामने आई, जिसमें स्थानीय फर्म "ग्रीन गार्डियंस" स्थानीय पर्यावरण पहल में सक्रिय हितधारक के रूप में उभरकर सामने आई।

मीर इकबाल, IEC राज्य सलाहकार SBM-G जम्मू एवं कश्मीर जैसी प्रमुख हस्तियों ने RDD क्षेत्र के अधिकारियों और सभ्य समाज के सदस्यों के साथ इस पहल की सहयोगात्मक प्रकृति को रेखांकित करते हुए इस आयोजन में अपना सहयोग दिया। पर्दे के पीछे, सचिव पंचायत कांजीउल्लार बिस्मा नज़ीर और GRS रमीज़ हैदर जैसे व्यक्तियों ने स्वच्छता बैंकों की स्थापना और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

तथापि, इस पहल को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ जिलों में अभी तक स्वच्छता बैंक ही नहीं खोले गए हैं। फिर भी, स्वच्छता बैंक पहल पूरे क्षेत्र में कचरा प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता पर अटल है।

ब्रांड एंबेसडर के रूप में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की सक्रिय भागीदारी से प्रेरित, स्वच्छता बैंक कांजीउल्लार के चल रहे प्रयास, इस क्षेत्र के लिए एक सापेक्षतया स्वच्छ, हरित भविष्य की दिशा में एक आशाजनक स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे-जैसे यह पहल आगे बढ़ेगी, अगले चरण में स्वच्छता बैंकों को रीसाइक्लिंग सुविधाओं से जोड़ा जाएगा जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान मिलेगा।

सुश्री अनु मल्होत्रा, महानिदेशक ग्रामीण स्वच्छता, जम्मू एवं कश्मीर, ने कचरा प्रबंधन के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए स्वच्छ और हरित वातावरण बनाने में स्वच्छता बैंकों के महत्व का पुरजोर समर्थन किया है। स्वच्छता बैंकों के पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रतीक के रूप में काम करने से, जम्मू एवं कश्मीर के समुदायों को इसी तरह की पहल को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे सभी के लिए एक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है।

यूपी की सनाहा ग्राम पंचायत: ODF PLUS मॉडल की दिशा में अग्रणी प्रगति

अयोध्या जिले में सरयू के पवित्र तट पर स्थित, सनाहा ग्राम पंचायत प्रगति की ज्वलंत मिशाल है, जिसने ODF PLUS मॉडल गांव बनने की यात्रा शुरू की है। इसके लिए वर्ष 2018-19 में इसे माननीय मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 350 घरों में 1820 की आबादी वाले इस गाँव को गंभीर चुनौतियों, विशेष रूप से जल प्रबंधन और कचरा निपटान से संबंधित, का सामना करना पड़ा। तथापि, ग्राम प्रधान श्रीमती रीना पांडे के नेतृत्व में, गाँव ने इन मुद्दों का निराकरण करने और व्यापक विकास हासिल करने के लिए परिवर्तनकारी कार्यों की एक श्रृंखला शुरू की।

वर्ष 2018-19 में खुले में शौच मुक्त (ODF) का दर्जा हासिल करने पर यह गांव ODF PLUS स्थिति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध रहा। उच्च जल स्तर और खराब जल निकासी के बावजूद, ग्राम प्रधान और स्थानीय अधिकारियों ने गंभीर मुद्दों से निपटने के लिए एक ग्राम कार्य योजना तैयार की। प्राथमिक चुनौतियों में से एक चुनौती गंदे पानी का प्रबंधन था। इसके साथ-साथ जलभराव और अपर्याप्त जल निकासी प्रणालियों की भी समस्या थी। अनुपचारित कचरा जल, ठोस कचरे के साथ, नदी को प्रदूषित कर रहा था, जिससे समुदाय के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो रहे थे।
इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, ग्राम प्रधान ने तरल और ठोस कचरा प्रबंधन दोनों पर ध्यान केंद्रित करने की पहल की। ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (SLWM) कार्य के लिए 5.36 लाख रुपये की क्रेडिट सीमा आवंटित की गई, SBM (G) के तहत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र की स्थापना के लिए 16.00 लाख रुपये से पूरक राशि की व्यवस्था की गई। बुनियादी ढांचे में सुधार को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें 2154 मीटर लंबी नालियों का निर्माण किया जाना भी शामिल था। साथ ही मलबे और तलछट को रोकने के लिए 21 रोधक मीटर लगाए गए, जिससे नदी को और प्रदूषित होने से बचाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, गंदे पानी के उचित निपटान की सुविधा के लिए 32 सोख गड्ढों का निर्माण किया गया, जिससे रुके हुए पानी और जलभराव की समस्याओं में काफी कमी आई।

व्यवस्थित ठोस कचरा प्रबंधन की शुरूआत में एक संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र (RRC), व्यक्तिगत और सामुदायिक खाद गड्ढों (NADEP) की स्थापना और नियमित कचरा संग्रह के लिए एक ई- रिक्शा की खरीद शामिल थी। कचरा पृथक्करण और निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे गाँव में रणनीतिक रूप से प्लास्टिक बैंक और कूड़ेदान रखे गए। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (CSC) के निर्माण और सभी निवासियों के लिए उचित स्वच्छता सुनिश्चित करने के साथ सामुदायिक सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वयं-सहायता समूह (SHGs) से एक समर्पित केयरटेकर को नियुक्त किया गया, उनकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक (600/- रुपये) प्रदान किया गया। पंचायत भवन विकासपरक गतिविधियों के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में उभरा, जिसकी देखरेख पंचायत सहायक करते थे। उन्होंने स्वच्छता प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं से सुसज्जित अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ शिक्षा और जागरूकता पहल को भी प्राथमिकता दी गई। गांव ने कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना के साथ प्रौद्योगिकी को अपनाया, जिससे समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान हो गई। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र की स्थापना ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जो प्लास्टिक कचरे के प्रसंस्करण के लिए मशीनरी से लैस है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने 300 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्र किया है, जिसमें 143 किलोग्राम प्लास्टिक को टुकड़ों में काटा गया और उन्हें बेचा गया है, जिससे ग्राम पंचायत के लिए राजस्व पैदा हुआ है।

ढांचागत सुधारों के अलावा, गांव ने अपनी दीवारों को ODF Plus से संबंधित संदेश देने वाले जीवंत दीवार चित्रों से सजाया, जिससे स्वच्छता और स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा मिला। गाँव के दृश्य परिवर्तन ने न केवल अपने निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि पड़ोसी समुदायों का भी ध्यान आकर्षित किया है, जिससे उन्हें सनाहा की सफलता की कहानी का अनुकरण करने के लिए प्रेरणा मिली है।

अंत में, सनाहा ग्राम पंचायत की ODF से ODF Plus मॉडल गांव तक की यात्रा जमीनी स्तर की पहल और समुदाय के नेतृत्व वाले विकास की शक्ति का परिवर्तनकारी उदाहरण है। कार्यसंबंधी योजना, नवाचार और सामूहिक प्रयास के माध्यम से, गांव ने कठिन चुनौतियों को पार किया है, जो समग्र विकास और टिकाऊ जीवन के एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में उभर रहा है।

SLWM, अयोध्या के डीसी श्री अभीरल पाठक और यूनिसेफ/SBM (G), उत्तर प्रदेश की राज्य सलाहकार श्रीमती तुहिना रॉय के इनपुट्स के साथ।

राज्य स्तरीय कार्यशाला: झारखंड में सूखा और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए रूपरेखा

पेयजल और स्वच्छता विभाग (DW&SD), SBM (G), झारखंड सरकार द्वारा HDFC बैंक, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन (CEE), नीड्स (NEEDS), और यूनिसेफ (UNICEF) के साथ साझेदारी में "झारखंड में सूखा और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए रूपरेखा" पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन 5 जनवरी 2024 को किया गया था, जिसमें झारखंड के सभी 24 जिलों के 180 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। विशिष्ट प्रतिभागियों में डॉ. नेहा अरोड़ा, IAS - मिशन निदेशक, SBM (G), झारखंड सरकार; श्री प्रभजोत सोढ़ी (MBE) - वरिष्ठ कार्यक्रम निदेशक, सर्कुलर इकोनॉमी, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन (CEE) दिल्ली; 30 से अधिक गांवों से नीड्स, कार्यकारी अभियंताओं, जिला समन्वयकों, जिला कार्यक्रम प्रबंधकों और ग्राम मुखियाओं की टीम शामिल थी।

कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में ब्लॉकों और गांवों के प्रतिनिधियों को संवेदनशील बनाना था, जिसका उद्देश्य पूरे झारखंड में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों (PWMU) के स्थायी और स्केलेबल मॉडल को कार्यान्वित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा विकसित करना था।

प्रतिभागियों ने PWMUS की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व सृजन प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया तथा उन्हें मौजूदा सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जोड़ा। कार्यशाला में ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर सूखे और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के बारे में चर्चा शामिल थी। इस आयोजन ने जागरूकता की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, संग्रह, परिवहन, अलगाव, रीसाइक्लिंग पद्धतियों और बाजार लिंकेज स्थापित करने में चुनौतियों सहित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। मंच ने विभिन्न राज्यों से विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) नीति और स्वच्छता केंद्र मॉडल जैसे सर्वोत्तम प्रथाओं और अभिनव दृष्टिकोणों को साझा करने की सुविधा प्रदान की।

श्री प्रभजोत सोढ़ी, वरिष्ठ कार्यक्रम निदेशक, चक्रीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण शिक्षा केंद्र द्वारा एक बातचीत सत्र प्लास्टिक और सूखा कचरा प्रबंधन पर केंद्रित था। उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक का प्रदर्शन किया और उनकी विशेषताओं के बारे में बताया और सभी प्रतिभागियों को कचरा, कचरे के प्रकार, स्रोत पृथक्करण का महत्व, MRF की स्थापना (2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक और 4 और अधिक ब्लॉक के क्लस्टर पर मॉडल के साथ), मशीनरी का चयन, सेवा भागीदारों का चयन, अनौपचारिक क्षेत्र का समावेश, कचरा संग्रह तंत्र, गांवों और पंचायतों का सामाजिक मानचित्रण, सामुदायिक स्वामित्व का महत्व और मजबूत निगरानी, रिपोर्टिंग और प्रलेखन का महत्व। उन्होंने एक गहन रणनीति और दृष्टिकोण साझा किया जिसे एचडीएफसी बैंक-सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन (CEE) परियोजना 'रूरल एंड अर्बन लैंडस्केप फ्री ऑफ ड्राई एंड प्लास्टिक वेस्ट' में कार्यान्वित किया जा रहा है।

बैठक के परिणाम

कार्यशाला का समापन झारखंड में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का समाधान करने के लिए एक समग्र और भागीदारी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर सभी प्रतिभागियों के बीच आम सहमति के साथ हुआ। प्रमुख संकल्पों में सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) पहल और प्रसार के लिए उपलब्ध प्लेटफार्मों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों के बीच जागरूकता और व्यवहारवादी परिवर्तन को बढ़ावा देना शामिल था। प्रतिभागियों ने एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपने संबंधित जिलों और गांवों में PWMU को लागू करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन के साथ कार्रवाई योग्य योजनाओं का मसौदा तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध किया। कार्यशाला प्लास्टिक कचरे से निपटने में सामूहिक प्रयास के लिए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में खड़ी है, जो झारखंड में एक स्थायी और अभिनव कचरा प्रबंधन मॉडल के लिए आधार तैयार करती है।

अधिक जानकारी के लिए: संपर्क करें

श्री प्रभजोत सोढ़ी; वरिष्ठ कार्यक्रम निदेशक (परिपत्र अर्थव्यवस्था) और निदेशक MRAI (माननीय) prabhjot.sodhi@ceeindia.org पर;

अमरप्रीत कौर, परियोजना अधिकारी-संचार और IEC, amarpreet.kaur@ceeindia.org

ग्राम पंचायतों में अग्रणी स्थायी SLWM चिकालिम, मोरमुगाओ तालुका गोवा

गोवा के रमणीय परिदृश्य के बीच, चिकालिम गांव ठोस कचरा प्रबंधन (SLWM) में नवाचार के एक प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो SBM-G की भावना का प्रतीक है।

गोवा के रमणीय परिदृश्य के बीच, चिकालिम गांव ठोस कचरा प्रबंधन (SLWM) में नवाचार के एक प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो SBM-G की भावना का प्रतीक है।

चिकालिम ग्राम पंचायत और रिस्पॉन्सिबल अर्थ फाउंडेशन (REF) के बीच एक सामूहिक प्रयास में, तीन हाउसिंग सोसाइटियों को कचरा प्रबंधन संबंधी रणनीतियों को अपनाने हेतु सराहना की गई है। जनवरी 2024 में शुरू किया गया, यह कार्यक्रम SLWM नियम 2016, भारत सरकार के थोक कचरा नियम 2018 और गोवा पंचायत उपनियमों के पालन में है, जो स्वच्छता और स्थिरता हेतु गांव के समर्पण के लिए एक प्रमाण के रूप में काम करना जारी रखता है। इस पहल के केंद्रबिंदु में आवास परिसरों के भीतर सामान्य कचरा भंडारण सुविधाओं की स्थापना शामिल है, जो पारंपरिक रूप से घर-घर जाकर संग्रह विधियों से कचरा एकत्रित किया जाता है। कचरा भंडारण को केंद्रीकृत करके, चिकालिम न केवल सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाता है, बल्कि SBM-G विजन के साथ संरेखित स्वच्छता और सामुदायिक जुड़ाव की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है।

चिकालिम के सरपंच ने कचरा भंडारण को केंद्रीकृत करने के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर दिया जो आवास समाजों के भीतर बाहरी कार्यकर्ता की उपस्थिति को कम करता है, सुरक्षा जोखिमों को कम करता है, और निवासियों के लिए एक सुरक्षित रहने के वातावरण को बढ़ावा देता है।

गोवा स्थित कचरा प्रबंधन कंपनी "यस इन माई बैकयार्ड" के स्थायी प्रबंधक डायलन फर्नांडीस ने इस केंद्रीकृत दृष्टिकोण के व्यापक लाभों को रेखांकित किया जो स्वच्छता और सौंदर्यशास्त्र को काफी बढ़ा सकता है, जबकि निवासियों को बिना सख्ती किए गए संग्रहण कार्यक्रम निर्धारित करना तथा यह अपनी सुविधानुसार अपने कचरे का निपटान करने के लचीलेपन को इंगित करता है।

पंचायत दक्षिण के उप निदेशक एवं SBM-G के राज्य समन्वयक प्रसिद्ध पी. नाइक ने चिकालिम पंचायत के निवासियों को उनके ईमानदार प्रयासों के लिए सराहना की और उन्हें आगे बढ़ने का सुझाव दिया जहां अन्य पंचायत सूट का पालन करती हैं, पूरे राज्य में स्थायी जीवन की दिशा में एक सामूहिक आंदोलन को बढ़ावा देती हैं।

इनोवाटिवा कचरा सहायता और प्रबंधन समाधान इस मिशन के लिए चिकालिम पंचायत के भागीदार हैं और अपने काम के माध्यम से वे ठोस और तरल कचरे दोनों के व्यापक रूप से उपचार के लिए उन्नत तकनीक को एकीकृत करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से, वे प्रभावी कचरा प्रबंधन के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं, तथा अधिक स्वच्छ, स्वस्थ समुदायों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

चिकालिम में यह सुव्यवस्थित कचरा निपटान प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि संग्रह दौर के दौरान किसी भी परिवार की अनदेखी न हो तथा समावेशिता और दक्षता को बढ़ावा मिले। जैसा कि चिकालिम स्थायी कचरा प्रबंधन प्रथाओं का नेतृत्व करता है, यह न केवल पड़ोसी समुदायों के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है, बल्कि स्वच्छ भारत के बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य में भी योगदान देता है। साथ मिलकर, हम एक अधिक स्वच्छ, हरित भविष्य तथा एक समय में एक केंद्रीकृत कचरा भंडारण सुविधा की ओर एक यात्रा शुरू कर सकते हैं, जो SBM-G पहल की भावना को प्रतिध्वनित करता है।

Sustainability goal of common waste storage set by Chicalim

TIMES NEWS NETWORK

The waste collected at the common point of housing societies will then be moved to the point from where it will be picked up by the civic body

Vasco: To promote setting up of common waste storage and segregation facilities within housing complexes, the Chicalim panchayat, in association with Responsible Earth Foundation (REF), has started identifying housing societies that would adopt the new and sustainable practice.

Under the new system, a housing complex will have a common waste storage facility rather than doorstep waste collection. The waste collected at the common point will then be moved to the point from where it will be picked up by the civic body concerned.

Chicalim sarpanch Kamla Prasad Yadav said that by centralising waste storage, the housing societies will not only enhance security and convenience but also promote cleanliness, environmental conservation, and community engagement. "All housing societies must have a progressive approach in waste management," Yadav said.

Chicalim panchayat has already identified three housing societies— Elements by Shantilal, Sky Panoramic Apartment and Bay Village—to implement govt-approved solid waste management practices.

Dylan Fernandes, business development manager of Yes In My Backyard (YIMBY), a waste management company based in Goa, said by consolidating waste at a common point, societies can minimise the entry of external workers onto their premises.

By maintaining waste at a central point, Fernandes said, societies will be able to significantly improve their cleanliness and aesthetics. One of the primary advantages of having centralised waste storage within a housing society is the convenience for residents, he said.

"With waste stored centrally, individuals can dispose of their trash at their own convenience without the constraints of adhering to rigid collection schedules," he said.

The new system will streamline the waste disposal process and also ensure that no household is overlooked during collection rounds, enhancing overall efficiency and reducing security risks.

सतत स्वच्छता का निर्माण: मध्य प्रदेश में कुशल मानव पूंजी विकास का एक केस स्टडी

परिचय:
मध्य प्रदेश का स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) 2.0 ग्रामीण स्वच्छता में एक परिवर्तनकारी कदम का प्रतीक है, जो तरल कचरा प्रबंधन (LWM) और मलीय कीचड़ प्रबंधन (FSM) पर जोर देता है। मलीय कीचड़ उपचार संयंत्रों (FSTP) और LWM संरचनाओं की आयोजना और प्रबंधन में कुशल कर्मियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, राज्य ने प्रत्येक जिले से इंजीनियरों और समन्वयकों की नियुक्ति करते हुए एक कार्यनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है। मिशन निदेशक सुश्री तन्वी सुंदरियाल के नेतृत्व में, सभी 52 जिलों के लिए विकास भागीदारों यूनिसेफ और वाटर एड के सहयोग से प्रशिक्षक प्रशिक्षण (ToT) का एक व्यापक तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

प्रक्रिया:
प्रशिक्षक प्रशिक्षण (ToT) कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण को संस्थागत बनाना, भागीदारी और वयस्क अधिगम के सिद्धांतों को नियोजित करना है। इंटरैक्टिव सत्रों और अनुभव के माध्यम से, प्रतिभागियों को कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त होते हैं, जिनमें DPR की तैयारी, FSTP के अनुरक्षण व रखरखाव, LWM संरचनाएं और सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार शामिल हैं। प्रशिक्षण स्थानीय चुनौतियों का समाधान करता है और भोपाल जिले के तूमदा और मुगलियाचैप पंचायतों जैसे सफल कार्यान्वयन को प्रदर्शित करता है।

मुख्य परिणाम:
इस कार्यक्रम द्वारा सफलतापूर्वक 106 इंजीनियरों और जिला/ब्लॉक समन्वयकों की क्षमता का निर्माण किया गया है, उन्हें जिला प्रशिक्षण प्रबंधन इकाई में एकीकृत किया गया है। ये प्रशिक्षित पेशेवर ब्लॉक स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में काम करेंगे, जो जमीनी स्तर पर ज्ञान का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त, 22 जिलों को प्रशिक्षण में शामिल किया गया है, जिससे 1700 प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। इस गति को बनाए रखने के लिए, निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक व्यापक योजना तैयार की गई है, जिसमें राज्य के विशेषज्ञ जिला स्तर पर सहायता प्रदान करते हैं।

भावी कार्यनीति व निष्कर्ष:
स्थायी स्वच्छता और तरल कचरा प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश की प्रतिबद्धता हितधारकों की क्षमता निर्माण और सामुदायिक जुड़ाव के प्रयासों के माध्यम से स्पष्ट लक्षित होता है। हितधारक प्रशिक्षण, नियमित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और निगरानी तंत्र में चल रहे निवेश प्रभावशीलता के लिए आवश्यक हैं। स्थानीय शासन संरचनाओं में LWM सिद्धांतों को एकीकृत करना और संबंधित विभागों के साथ आगे अभिसरण स्थिरता सुनिश्चित करेगा। अपने अभिनव दृष्टिकोण का लाभ उठाकर, मध्य प्रदेश ग्रामीण समुदायों के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ भविष्य की ओर अग्रसर हो सकता है।
श्री कृपाशंकर यादव, टीम लीडर, PMU और सुश्री ईशा सिंह, CB और IEC विशेषज्ञ, PMU-SBM-G, इनपुट्स के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: सुश्री ईशा सिंह, CB और IEC विशेषज्ञ, PMU-SBM-G, swsmmp@gmail.com

ईंधन स्थिरता: एरुमेली पुलिस शिविर, केरल में गोबर्धन बायोगैस क्रांति

केरल के कोट्टायम जिले के एरुमेली पुलिस शिविर में गोबरधन बायोगैस संयंत्र के कार्यान्वियन के माध्यम से स्वच्छता और लागत बचत उपायों के एक नए युग की शुरुआत की गई। पहले प्रदूषण के मुद्दों और LPG पर अधिक खर्च से जूझते हुए, शिविर अधिकारी अब संयंत्र द्वारा किए गए उल्लेखनीय सुधारों का अवसर प्राप्त कर रहे हैं।

गैस सिलेंडरों की लगातार रिफिल और जलाऊ लकड़ी पर भारी खर्च के दिन लद गए हैं। संयंत्र के कचरे को ईंधन में बदलने से न केवल लंबे समय से चली आ रही प्रदूषण की समस्या का समाधान होता है, बल्कि शिविर के मासिक ईंधन खर्च में भी काफी कमी आई है। सबरीमाला तीर्थयात्रा के दौरान 900 लोगों और नियमित दिनों में अतिरिक्त 200 लोगों की सेवा करने की क्षमता के साथ, संयंत्र स्थिरता और दक्षता के एक प्रतीक के रूप में उभरा है।

वर्ष 2022-23 में SBM(G) चरण-II के तहत 9.5 लाख रुपये की लागत से निर्मित, गोबरधन संयंत्र नवीन कचरा प्रबंधन समाधानों की शक्ति का एक प्रमुख आधार है। 200 किलोग्राम क्षमता के साथ कार्य करते हुए, संयंत्र प्रतिदिन औसतन 180 किलोग्राम कचरे का प्रसंसाधित करता है, जिससे खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली लगभग 7 घन मीटर गैस प्राप्त होती है। इससे LPG की लागत में लगभग 37,500 रुपये की मासिक बचत होती है।

भूमि की कमी से उत्पन्न प्रारंभिक चुनौतियों के बावजूद, वन विभाग द्वारा पांच सेंट भूमि के आवंटन से ग्राम पंचायत के ठोस प्रयासों से संयंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। आज, एरुमेली पुलिस शिविर स्थायी कचरा प्रबंधन प्रथाओं के एक मॉडल के रूप में स्थापित है, जो राज्य भर में इसी तरह के प्रतिष्ठानों के लिए एक स्वच्छ, अधिक कुशल भविष्य की झलक पेश करता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: अब्राहम थॉमस रंजीत, कार्यक्रम अधिकारी (IEC), atrmsw@gmail.com

मुर्हा गांव, पश्चिम बंगाल: सतत जीवन समुदाय के नेतृत्व वाली शून्य अपशिष्ट पहल का एक प्रकाशस्तंभ

भारत में दार्जिलिंग जिले के शांत भू-परिदृश्य के बीच स्थित मुर्हा गांव समुदाय-संचालित स्थिरता की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए एक साक्ष्य के रूप में प्रज्वलित होता है। 500 परिवारों के साथ, यह गांव आशा की किरण के रूप में खड़ा है, यह दर्शाता है कि कैसे सामूहिक कार्रवाई ग्रामीण बसावटों को शून्य-अपशिष्ट जीवन के मॉडल में बदल सकती है।

सामुदायिक जुड़ाव और ज़िम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन: मुर्हा गांव की सफलता के केंद्र बिंदु में कचरा प्रबंधन में इसके निवासियों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। स्थानीय रूप से तैयार किए गए कूड़ेदानों के व्यापक उपयोग के माध्यम से, उपलब्ध ड्रमों और बांस से निर्मित कूड़ेदान, समुदाय जिम्मेदार अपशिष्ट निपटान प्रथाओं को बढ़ावा देता है। स्वामित्व और जवाबदेही की इस भावना को ग्रामीणों के साप्ताहिक सामूहिक सफाई प्रयासों द्वारा और अधिक उदाहरण पेश किया गया है, जो स्वच्छ और प्राचीन वातावरण बनाए रखने के लिए उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है।

सतत प्रथाओं को अपनाना
घरेलू खाद:

अपने शून्य-अपशिष्ट लक्ष्यों के अनुरूप, मुर्हा गांव के निवासी बायोडिग्रेडेबल कचरे की घरेलू खाद बनाने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। इस कार्य से न केवल कचरा कम होता है बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर खाद का उत्पादन भी होता है, कृषि स्थिरता को बढ़ावा देता है और संसाधन प्रबंधन के चक्र को पूरा करता है।

प्लास्टिक मुक्त वातावरण:

उल्लेखनीय रूप से, मुर्हा गांव एक प्लास्टिक-मुक्त वातावरण का दावा करता है, जिसमें प्लास्टिक का एक भी टुकड़ा अपने परिसर में कूड़ा नहीं डालता है। यह उपलब्धि स्थायी जीवन प्रथाओं और पर्यावरण संरक्षण के लिए समुदाय की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

सतत पहल का प्रदर्शन

स्थानीय ग्रामीणों के साथ बातचीत के दौरान, आगंतुक पहली बार स्थायी जीवन में गांव की उपलब्धियों को देखते हैं। स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों से लेकर शून्य-अपशिष्ट विवाह समारोहों की मेजबानी करने तक, मुर्हा विलेज गर्व से समग्र स्थिरता के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करता है, दुनिया भर के समुदायों को इस वातावरण का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। स्थानीय समिति समाज मुर्हा गांव की जमीनी स्तर की पहल का नेतृत्व करता है, जो निवासियों को पर्यावरणीय जिम्मेदारी और टिकाऊ जीवन प्रथाओं को अपनाने के लिए सशक्त बनाता है। शिक्षा, सामुदायिक जुड़ाव और संसाधन सुविधा के माध्यम से, यह संगठन सकारात्मक बदलाव को उत्प्रेरित करता है, जिससे मुर्हा की यात्रा शून्य-अपशिष्ट भविष्य की ओर बढ़ जाती है।

सतत जीवन के लिए एक मॉडल

मुर्हा गांव की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, जिसमें स्थानीय रूप से तैयार किए गए डस्टबिन, 'डोको' और समुदाय संचालित सफाई पहल जैसे रविवार को सफाई शामिल है और प्रभावी अपशिष्ट कमी और निपटान कार्यनीतियों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है। गाँव में घरेलू खाद बनाने का संसाधन प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो कृषि स्थिरता और मिट्टी के संवर्धन में योगदान देता है। सामुदायिक सशक्तिकरण: स्थानीय समिति समाज द्वारा संचालित, मुर्हा गांव स्थायी जीवन और पर्यावरणीय प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देने में सामुदायिक सशक्तिकरण की शक्ति का उदाहरण पेश करता है। गांव प्लास्टिक भंडारण इकाइयों को स्थापित करने का इरादा रखता है जो आर्थिक अवसरों को सक्षम करेगा।

अंत में, मुर्हा गांव स्थायी जीवन के लिए एक खाका के रूप में प्रस्तुत करता है और यह दर्शाता है कि कैसे सामूहिक कार्रवाई, सामुदायिक सशक्तिकरण और पर्यावरणीय प्रबंधन ग्रामीण बसावटों को शून्य-अपशिष्ट जीवन के मॉडल में बदल सकता है। जैसा कि हम मुर्हा की यात्रा से प्रेरणा लेते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि सतत विकास केवल एक लक्ष्य नहीं है बल्कि साझा दृष्टि और सामूहिक प्रयास के माध्यम से प्राप्त करने योग्य एक ठोस वास्तविकता है। बता दें कि मुर्हा गांव दुनिया भर के समुदायों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करता है, जो एक अधिक जीवंत, लचीला और पर्यावरण के प्रति जागरूक समाज की ओर मार्ग प्रशस्त करता है।

राज्य के झरोखे से

के. नागेंद्र प्रसाद

मैं कर्नाटक के मिशन निदेशक के रूप में राज्य में हमने जो उल्लेखनीय प्रगति की है, उसे साझा करते हुए हम इसके लिए आभारी हैं जो विशिष्ट कार्य के रूप में आते हैं वे हैं मलीय कीचड़ प्रबंधन (FSM) और स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (SGLR) प्रणाली।

संपूर्ण स्वच्छता की दिशा में हमारी यात्रा में, कर्नाटक, साहसिक कदम आगे बढ़ा रहा है। FSM के साथ, हम न केवल उपचार सुविधाओं को बड़ा कर रहे हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि 77 मौजूदा एसटीपी सह-उपचार सुविधाओं से जुड़े हों, कुल 234 उपचार सुविधाओं की ओर बढ़ रहे हैं। यह राज्य भर में स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए हमारी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। विभिन्न स्तरों पर मार्गदर्शन और नियमित समीक्षा हमें आगे की योजना बनाने और पहले से अधिकृत चुनौतियों से निपटने में मदद करती है।

MCLR प्रणाली को अपनाना स्थायी पर्यटन के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है।

केंद्र द्वारा निर्देशित, हम राज्य के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इस प्रयास में भाग लेने वाले 182 से अधिक होटल और होमस्टे प्रतिष्ठान हैं। कर्नाटक इस परिवर्तनकारी पहल में सबसे आगे है जो आतिथ्य क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की संस्कृति को स्थापित करने पर केंद्रित होता है। जैसे-जैसे हम संपूर्ण स्वच्छता की ओर अग्रसर हैं, इस तरह की पहल हमें सभी के लिए एक स्वच्छ, हरित तथा अधिक टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देती है।

संक्षेप में एसबीएम

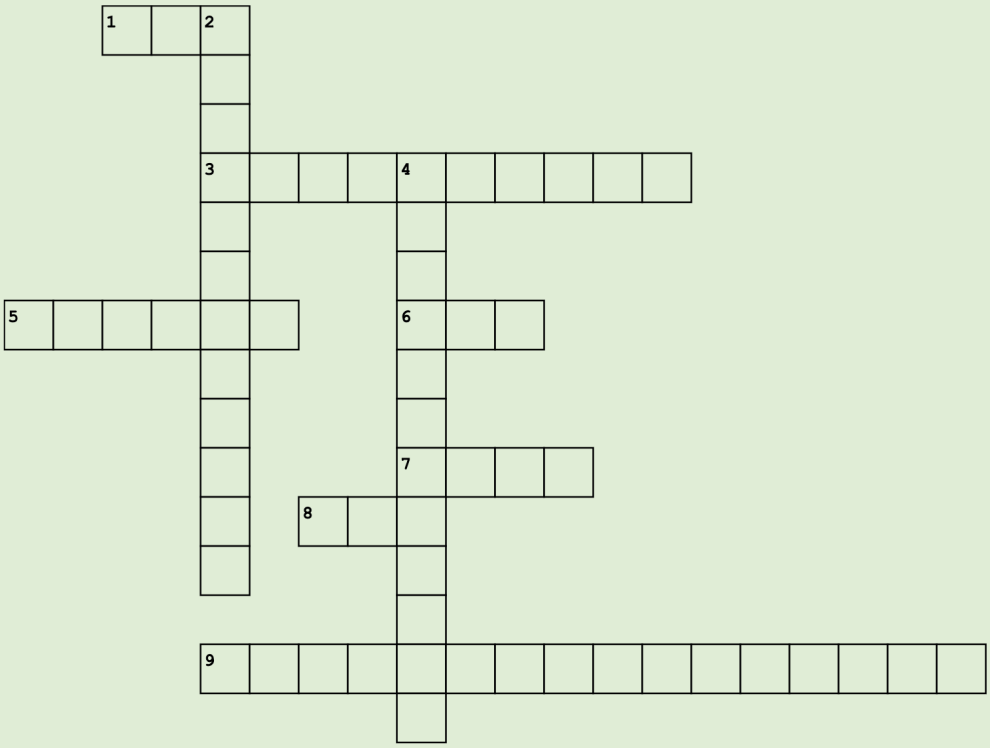

Across

1. Annual campaign for shramdaan

3. method of solid waste management

5. Campaign for construction of community soak pits for grey water management under SBM(G)

6. collection, storage, and disposal of plastic waste

7. Collaborative system aimed to uphold sanitation standards for responsible tourism

8. safe collection, treatment, and disposal of faecal waste under SBM(G)

9. Designated area where waste is sorted recycling, composting, or disposal for SBM(G)

Down

2. grassroots volunteers who drive community involvement under SBM(G)

4. SBM Phase II objective

स्वच्छता समाचार के अगले अंक में योगदान करने के लिए, हर महीने की 15 तारीख से पहले **swachhbharat@gov.in** अपनी प्रस्तुति साझा करें।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

विशेष सचिव का कार्यालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार।

चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
फोनः 011–24362192 | ईमेलः arun.baroka@nic.in